भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4120
उत्तर देने की तारीख 18.08.2025

सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रचार

4120. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों की पहचान और सारणीकरण के लिए उपयोग किए गए मानदण्डों और पद्धति का ब्यौरा क्या है और क्या इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया है;

(ख) स्थानीय आबादी के बीच इन पुस्तकालयों के प्रचार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जागरूकता अथवा आउटरीच गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे पुस्तकालयों के पूर्ण पते सहित व्यापक सूची है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह सूची जनता की जानकारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपलब्ध है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुस्तकालय' राज्य सूची के अंतर्गत आता है और सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं।

तथापि, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन,राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुस्तकालय प्राधिकरणों के सक्रिय सहयोग से, विभिन्न अनुमोदित समतुल्य और गैर-समतुल्य स्कीमों के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) स्कीम का क्रियान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत *एनएमएल मॉडल पुस्तकालय घटक के अंतर्गत मौजूदा पुस्तकालयों के उन्नयन* हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है/ इस घटक के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा चिन्हित छह पुस्तकालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य प्राधिकरणों की सिफारिशों के आधार पर और राज्य निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय को भी सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल चार प्रमुख क्षेत्रों: अवसंरचना में सुधार; प्रौद्योगिकी का उन्नयन और सेवाओं का आधुनिकीकरण; दिव्यांगजन समूहों के लिए सुविधाओं का सृजन; और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पठन संसाधनों की खरीद तथा प्रचार एवं आउटरीच कार्यक्रम पर केंद्रित है।

(ख): राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, मोबाइल पुस्तकालयों के संचालन हेतु सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पठन आदतों को बढ़ावा देना और वंचित समुदायों तक पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करना है। जिला और ब्लॉक स्तर पर पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों और पठन प्रोत्साहन गतिविधियों के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं सहित विविध उपयोगकर्ता समूहों को आकर्षित किया जा सके। उपयोगकर्ता की भागीदारी और सेवा सुपुर्दगी को बढ़ाने के लिए, आरआरआरएलएफ अवसंरचना के उन्नयन, फर्नीचर, आईसीटी उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के माध्यम से पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण का समर्थन करता है, जिससे स्थानीय आबादी के बीच पुस्तकालयों की दृश्यता, पहुँच और उपयोगिता में सुधार होता है।

इसके अलावा, आरआरआरएलएफ द्वारा हाल ही में शुरू किया गया *राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय रजिस्टर* देश के विभिन्न भागों में पुस्तकालयों की उपस्थिति के बारे में सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है और स्थानीय नागरिकों के बीच उनके आसपास के क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) स्कीम के अंतर्गत, *स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पठन संसाधनों की खरीद और समर्थन एवं आउटरीच कार्यक्रमों* के उप-घटक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें स्थानीय मांग के अनुसार पुस्तकों, ई-पुस्तकों, ऑडियो/वीडियो संग्रह, पत्रिकाओं और अन्य संसाधनों की खरीद के लिए सहायता शामिल है; और हितधारक की भागीदारी, सिविल सोसाइटी के साथ सहयोग, प्रश्नोत्तरी, रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताएं, मॉडल-निर्माण, संगीत प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, स्थानीय मीडिया में पुस्तकालय गतिविधियों का प्रचार और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थानीय स्कूलों में विस्तार काउंटर खोलने जैसे समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता शामिल है। प्रत्येक राज्य

केंद्रीय पुस्तकालय के लिए 3.00 लाख रू., प्रत्येक जिला पुस्तकालय के लिए 2.00 लाख रू. और संस्कृति मंत्रालय के प्रत्येक पुस्तकालय के लिए 4.20 लाख रू. तक की सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ) के माध्यम से हाल ही में देश भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक व्यापक, राष्ट्रीय स्तर का गतिशील डेटाबेस संकलित और अनुरक्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

****